

GS PAPER I

1. देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में 1 प्रतिशत की कमी :

देश के 91 प्रमुख जलाशयों में 113.034 बीसीएम (अरब घन मीटर) जल का संग्रहण आंका गया। यह इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 72 प्रतिशत है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के कुल संग्रहण का 130 प्रतिशत तथा पिछले दस वर्षों के औसत जल संग्रहण का 99 प्रतिशत है।

इन 91 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 157.799 बीसीएम है, जो समग्र रूप से देश की अनुमानित कुल जल संग्रहण क्षमता 253.388 बीसीएम का लगभग 62 प्रतिशत है। इन 91 जलाशयों में से 37 जलाशय ऐसे हैं जो 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ पनबिजली संबंधी लाभ देते हैं।

क्षेत्रवार संग्रहण स्थिति

उत्तरी क्षेत्र

उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान आते हैं। इस क्षेत्र में 18.01 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले छह जलाशय हैं, जो केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की निगरानी में हैं। 03 नवंबर, 2016 को जारी जलाशय संग्रहण बुलेटिन के मुताबिक, इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 12.06 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 67 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 77 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 76 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कमतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी कमतर है।

पूर्वी क्षेत्र

पूर्वी क्षेत्र में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा आते हैं। इस क्षेत्र में 18.83 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 15 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। 03 नवंबर, 2016 को जारी जलाशय संग्रहण बुलेटिन के मुताबिक, इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 15.77 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 84 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 64 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 74 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण बेहतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी बेहतर है।

पश्चिमी क्षेत्र

पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात तथा महाराष्ट्र आते हैं। इस क्षेत्र में 27.07 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 27 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। 03 नवंबर, 2016 को जारी जलाशय संग्रहण बुलेटिन के मुताबिक, इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 23.14 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 85 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 56 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 78 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण बेहतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी बेहतर है।

मध्य क्षेत्र

मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ आते हैं। इस क्षेत्र में 42.30 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 12 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। 03 नवंबर, 2016 को जारी जलाशय संग्रहण बुलेटिन के मुताबिक, इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 37.80 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 89 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 69 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 68 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण बेहतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी बेहतर है।

दक्षिणी क्षेत्र

दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश (एपी), तेलंगाना (टीजी), एपी एवं टीजी (दोनों राज्यों में दो संयुक्त परियोजनाएं), कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु आते हैं। इस क्षेत्र में 51.59 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 31 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। 03 नवंबर, 2016 को जारी जलाशय संग्रहण बुलेटिन के मुताबिक, इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 24.26 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 47 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 32 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 72 प्रतिशत था। इस तरह चालू वर्ष में संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए संग्रहण से बेहतर है, लेकिन यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से कमतर है।

पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण बेहतर है उनमें पंजाब, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एपी एवं टीजी (दोनों राज्यों में दो संयुक्त परियोजनाएं), आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं कर्नाटक शामिल हैं। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण बराबर है उनमें उत्तराखंड शामिल है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण कमतर है उनमें हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं।

GS PAPER II

GENERAL STUDIES HINDI

1. Target 2020 Olympic

- खेल विभाग ने एनएसएफ) National sports federations) को 30 नवंबर, 2016 तक 2020 के टोक्यो ओलम्पिक खेलों के लिए पदक हासिल कर पाने वाले खिलाड़ियों और उनके सहयोगी स्टाफ की पहचान करने की सलाह दी है। इससे महत्वपूर्ण संभावित खिलाड़ी को समर्पित विश्व स्तरीय सहयोगी स्टाफ उपलब्ध कराना सुनिश्चित होगा ताकि, सुसंगत टीम के रूप में कार्य कर वांछित परिणाम हासिल किए जा सकें।
- एनएसएफ को आवश्यक वित्तीय सहायता टारगेट ओलम्पिक पोडियम योजना)टीओपीएस (के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल विकास कोष) एनएसडीएफ (से प्राप्त होगी।

- NSFs ओलंपिक पदक जीत सकने वाले संभावित खिलाड़ियों व सहयोगी स्टाफ का चयन ,उनके पिछले 6 माह के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर करेगा - NSFs चयन व समीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी रखेगा तथा विस्तृत विवरण वेबसाइट पर जारी करेगा ।
- इससे खिलाड़ियों को विदेशी व देशी विशेषज्ञ कोचो से प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा तथा खेलो में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाया जा सकेगा ।
- इससे खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने के लिए अधिक लक्षित किया जा सकेगा ।

****** पिछले कुछ समय में ओलंपिक खेलो में प्रदर्शन सुधारने हेतु किए गये सरकारी प्रयास :-**

- 2020 टोक्यो ओलंपिक में 50 पदक जीतने की संभावना खोजने हेतु कार्य बल (Task force) का गठन।
- नीति आयोग ने ओलंपिक प्रदर्शन सुधारने हेतु 20 सूत्री कार्य योजना पेश की ,जिसमें मुख्यतः 10 खेलो पर फोकस करने , राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक को कानूनी रूप देने, अल्पावधि, मध्यावधि, व दीर्घावधि लक्ष्य निर्धारण करने ,युवा खेल बीमा योजना बनाने , प्रत्येक राज्य में कम से कम एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने, तथा नियमित अंतराल पर खिलाड़ियों, खेल संस्थाओं व प्रशिक्षकों के प्रदर्शन की समीक्षा करने की बात कही गई है।

निष्कर्ष) conclusion):- रियो-ओलम्पिक में पी.वी.सिंधु व साक्षी मलिक के अतुलनीय प्रदर्शन ने विश्व में सबसे अधिक युवा आबादी वाले देश की जन-आकांक्षाओं को जिंदा रखने में अविस्मरणीय योगदान दिया है।

- ओलम्पिक में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन ने सरकारी नीतियों की पंगुता व आमजन तथा कॉरपोरेट जगत की खेलों के प्रति बेरुखी को जाहिर किया है।
- **बाधक तत्व :** विद्यालय , महाविद्यालय व विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों के आयोजनों तथा प्रशिक्षण की कमी, ब्लॉक पंचायत व जिला स्तर पर एकीकृत खेल परिसरों का अभाव, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक खेल उपकरणों, ढांचे व वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित प्रशिक्षण का अभाव , नैसर्गिक क्षमताओं से ओतप्रोत गांव-ढाणी की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने वाली योजनाओं का अभाव , ओलम्पिक , एशियाई, व राष्ट्रमंडल खेलों में खेलने वाले खिलाड़ियों व पदक विजेताओं के लिए नाकाफी प्रोत्साहन राशि , भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप खेल चयन का अभाव , खेलों के महत्व को रेखांकित करने वाले पाठ्यक्रम का अभाव, तथा खेलों को केरियर विकल्प व जीवन के अभिन्न अंग के रूप में स्थापित करने वाली जन चेतना की अनुपलब्धता आदि भारत में खेलों के विकास में बाधक तत्व है।

What to be done: जरूरत है सरकार खेलों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास व खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु अधिक फंड आवंटित करे , पी.वी.सिंधु, सायना

नेहवाल, अभिनव बिंद्रा, साक्षी मलिक, तथा दीपा कर्माकर जैसे खिलाड़ियों को युवाओं के मध्य रोल मॉडल के रूप प्रचारित करे, तथा नई खेल नीति बनाकर गांव-ढाणी तक के युवाओं की खेलों में भागीदारी सुनिश्चित करे ताकि टोक्यो ओलम्पिक में भारत का प्रदर्शन बेहतर किया जा सके ।

2. पूरे देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू

- **केरल और तमिलनाडु** द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लागू किए जाने के साथ अब यह अधिनियम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया है।
- इसके परिणामस्वरूप 81.34 करोड़ लोगों को 2 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रूपये प्रति किलोग्राम के भाव से चावल मिलेगा। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से सक्रियता के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने का आग्रह किया था।
- केंद्र अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में आगे सुधार करने पर फोकस करेगा। इसमें शुरू से अंत तक प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण शामिल है। इसके लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज में पारदर्शिता लाना महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता है ताकि अनाजों की चोरी और डायवर्जन रोका जा सके।
- **डिजिटलीकरण** : सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चोरी मुक्त बनाने के लिए केंद्र की ओर से अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में लाभार्थी का डेटा का डिजिटलीकरण किया गया है। इसमें लाभार्थी के स्तर तक सूचना उपलब्ध है और सूचना पब्लिक डोमेन में है। 28 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में अनाजों का ऑनलाइन आवंटन किया जा रहा है और 18 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्यान्न सप्लाई की पूरी श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। राशनकार्डों का आधार से 100 फीसदी जोड़ने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। अभी 71 प्रतिशत राशनकार्ड आधार से जुड़े हैं। एफसीआई का खाद्यान्न नुकसान कम होकर 0.04 प्रतिशत रह गया है और एफसीआई के प्रमुख डीपो ऑनलाइन कर दिये गए हैं।
- **योजना का प्रारूप** : बेहतर लक्ष्य और खाद्यान्नों के चोरी मुक्त वितरण की दिशा में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना दो अलग-अलग रूप में चलाए जा रही हैं।
 - पहली पद्धति में लाभार्थी के बैंक खाते में **खाद्यान्न सब्सिडी नकद रूप** में अंतरित की जा रही है। लाभार्थी अपनी पंसद के अनुसार बाजार से अनाज खरीद सकते हैं। यह प्रयोग चंडीगढ़, पुडुचेरी तथा दादरा और नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों में शुरू किया गया है।
 - दूसरे तरीके में **उचित मूल्य की दुकानों को स्वचालित** करना है ताकि बिक्री के इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट (इ-पीओएस) उपकरण के माध्यम से वितरण के समय लाभार्थी के प्रमाणीकरण के साथ अनाजों का वितरण किया जा सके। इस व्यवस्था में परिवार को दिए जाने वाले अनाज की मात्रा की इलेक्ट्रॉनिक जानकारी होती है। 31.10.2016 तक 1,61,854 उचित मूल्य की दुकानों में इ-पीओएस उपकरण काम कर रहे हैं।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज को सहज बनाने के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता दी जा रही है ताकि सरकारें राज्य के अंदर परिवहन खर्च और खाद्यान्नों के उतार-चढ़ाव तथा डीलर के मार्जिन का खर्च वहन कर सकें। उचित मूल्य के दुकानों को डीलरों की

मार्जिन के लिए सहायता में उचित मूल्य दुकान पर डीओएस उपकरण लगाने और चलाने के लिए सहायता भाग शामिल है।

- भारत सरकार द्वारा 2016-17 में अब तक राज्य सरकारों को 1874 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वर्तमान कवरेज पर अधिनियम के अंतर्गत राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों का मासिक आवंटन लगभग 45.5 लाख टन है और इसमें 11,726 करोड़ रुपये प्रति माह की सब्सिडी और लगभग 1,40,700 करोड़ रुपये सालाना की सब्सिडी है।
- गन्ना बकायों के बारे में श्री पासवान ने कहा कि 2014-15 का बकाया 21 हजार करोड़ रुपये था जो घटकर 205 करोड़ रुपये रह गया है। चना को छोड़कर दालों की कीमतों में गिरावट आई है। गेहूं के मूल्यों के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार ने एफसीआई ओएमएस योजना के अंतर्गत घरेलू बाजार में बिक्री के लिए अतिरिक्त 10 लाख टन गेहूं जारी करने का निर्णय लिया है।

3. वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग (Value capture financing)

- वर्तमान शहरी बुनियादी ढांचे के विस्तारीकरण से जुड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए संसाधनों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास मंत्रालय जल्द ही वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग के अभिनव तरीके के जरिए संसाधन जुटाने के लिए एक नीतिगत (वीसीएफ) रूपरेखा पेश करेगा।
- **What is benefit:** इससे राज्यों एवं स्थानीय सरकारों को अपने प्रभाव वाले चिन्हित क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश और नीतिगत पहलों से जमीन एवं अन्य संपत्तियों जैसे कि इमारतों की कीमतों में हुई वृद्धि के एक हिस्से का दोहन करके संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।
- **Methods:** वीसीएफ के विभिन्न तरीके ये हैं भूमि मूल्य कर, भूमि के उपयोग में बदलाव के लिए शुल्क, समुन्नति शुल्क, विकास शुल्क, विकास अधिकारों का हस्तांतरण, फ्लोर स्पेस इंडेक्स एवं फ्लोर एरिया रेशियो संबंधी छूट पर प्रीमियम, खाली पड़ी भूमि पर कर, टैक्स में वृद्धि का वित्तपोषण, भूमि अधिग्रहण के लिए क्षेत्रीकरण संबंधी छूट और लैंड पूलिंग प्रणाली।

4. प्रधानमंत्री युवा योजना

- कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के दूसरे स्थापना दिवस के अवसर पर यह योजना घोषित की गई
- पांच साल) 2016-17 से 2020-21 तक (की अवधि में 499.94 करोड़ की परियोजना लागत से यह योजना 3050 संस्थानों के माध्यम से 7 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को उद्यमशीलता शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी।
- यह सूचना और संरक्षक नेटवर्क, क्रेडिट, इनक्यूबेटर और एक्सीलेटर तक आसान पहुँच और युवाओं के लिए एक मार्ग का सृजन करने में सहायता प्रदान करेगी।
- प्रधानमंत्री युवा योजना के अधीन उच्च शिक्षा के 2200 संस्थान) कॉलेज, विश्वविद्यालय और प्रमुख संस्थान, 300 स्कूल, 500 आईटीआई और 50 उद्यमिता विकास केंद्र मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज) एमओओसी (के माध्यम से शामिल हैं।

5. भारत तपेदिक बीमारी उन्मूलन के लिए अनुसंधान कार्य में अग्रणी

A look on Data:

तपेदिक भारत की एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। (टीबी)विश्व में भारत पर तपेदिक का बोझ सबसे अधिक है।

- इस बीमार से प्रत्येक तीन मिनट में दो भारतीय और रोजाना 1,000 लोगों की जान चली जाती है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अक्टूबर 2016 में जारी वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट में टीबी बीमारी की घटनाओं का आकलन किया गया यानी 2015 में टीबी के 2.8 मिलियन नए मामले सामने आए और तपेदिक से मरने वाले मरीजों की संख्या एचआईवी पॉजिटिव लोगों की मृत्यु को छोड़कर 2015 में 478,000 तथा 2014 में 483,000 रही।

अनुसंधान कार्य

ICMR की अग्रणी पहल भारत टीबी अनुसंधान और विकास निगमका उद्देश्य टीबी के लिए नए (आईटीआरडीसी) साधन(औषधि), निदान और टीके विकसित करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को एक साथ (औषधि) लाना है। निगम का विजन नए साधनों, निदान और टीके के विकास में निवेश करके भारत से तपेदिक का (साथ विश्व को समाधान प्रदान करना है।- उन्मूलन करने के साथ

Other Measures:

माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशन में टीबी उन्मूलन को प्राथमिकता के तौर पर लिया गया है। उद्देश्य टीबी के नए मामलों में 95 प्रतिशत की कमी लाना और टीबी से मृत्यु में 95 प्रतिशत की कमी लाना है। उन्होंने कहा कि उपचार दरों में सुधार और नए मामलों में तेजी से कमी लाने के लिए अनुसंधान कार्य में तेजी लाई जाएगी

GS PAPER III

1. राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा मैड्रैक्स गोलियां (मेथाकालोन) जब्त :

- नशीली दवाओं एवं मादक पदार्थों की एक सबसे बड़ी जब्ती के तहत केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की शीर्ष तस्करी रोधी एजेंसी राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) (के अधिकारियों ने लगभग 23.5 मीट्रिक टन मैड्रैक्स गोलियां जब्त (मेथाकालोन) की हैं, जो एनडीपीएस नियम, 1985 की अनुसूची-1 के तहत एक प्रतिबंधित मादक पदार्थ है।

PRIZED CATCH

A joint team of sleuths has unearthed a large cache of Mandrax tablets in Udaipur

What is Mandrax?

- ➔ A banned psychotropic substance
- ➔ A depressant; overdose can lead to coma and death
- ➔ It is used as a recreational drug in Africa and Asia
- ➔ It is commonly known as M-pills, buttons or smarties
- ➔ The substance is smoked mixed with cannabis



HUGE HAUL: Chairman of Central Board of Excise and Customs (CBEC) Najib Shah (right), with Director-General of the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) Jayant Misra, at a press conference in New Delhi on Monday. — PHOTO: V. SUDERSHAN

- यह न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया में मेथाकालोन की अब तक की एक सबसे बड़ी जब्ती है।
- मैड्रैक्स का मुख्य कच्चा माल एसिटिक एनहाइड्राइड है

- मेथाक्वालोन एक अवसाद है, जिसकी ज्यादा खुराक लेने पर संबंधित व्यक्ति कोमा में जा सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। इसे आम तौर पर मैड्रैक्स, एमपिल्स-, बटन, या स्मार्टीज के रूप में जाना जाता है।

2. प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव-विविधता कांग्रेस

आईएसी 2016 का आयोजन 6-9 नवंबर 2016 तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस कांग्रेस में 60 देशों से लगभग 900 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में कृषि जैवविविधता प्रबंधन और आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका के बारे में बेहतर समझ विकसित करने से संबंधित चर्चा की जायेगी।

****प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव-विविधता कांग्रेस का आयोजन भारत में क्यों ?

प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैवविविधता कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में ईसा पूर्व 9000 वर्षों से खेती और पशुपालन का कार्य आरंभ हो चुका था। भारत में विशिष्ट पौधों और जीवों की विविधता होने के कारण यह महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। इसके अतिरिक्त 34 वैश्विक जैवविविधता हॉटस्पॉट में से चार भारत में स्थित हैं -हिमालय, पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्वी और निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा भारत, फसलीय पौधों की उत्पत्ति का विश्व के आठ केंद्रों में एक प्रमुख केंद्र है और वैश्विक महत्व की कई फसलों की विविधता का द्वितीयक केंद्र है।

*** कृषि जैव- विविधता का महत्व

- विश्व की बढ़ती आबादी की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में कृषि जैवविविधता के संरक्षण से टिकाऊपन बनाए रखने पर इस अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैवविविधता कांग्रेस में प्रकाश डाला जायेगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के साथ ही वर्ष 2050 तक 9.7 अरब वैश्विक आबादी (यून डेसा, 2015) की 70 प्रतिशत अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए टिकाऊ कृषि उत्पादन के विषय में भी चर्चा जायेगी।
- कृषि जैवविविधता ही सतत कृषि विकास का आधार है और वर्तमान तथा भावी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है। वैश्विक कुपोषण, जलवायु परिवर्तन, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, जोखिम कम करना और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें इन बहुमूल्य संसाधनों का संरक्षण करना होगा, क्योंकि हमारी कृषि पद्धति में इनसे आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति होती है और लोगों को आजीविका भी मिलता है।
- कृषि जैवविविधता ही सतत कृषि विकास का आधार है और वर्तमान तथा भावी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है। वैश्विक कुपोषण, जलवायु परिवर्तन, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, जोखिम कम

करना और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें इन बहुमूल्य संसाधनों का संरक्षण करना होगा, क्योंकि हमारी कृषि पद्धति में इनसे आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति होती है और लोगों को आजीविका भी मिलता है।

- मानव आहार में जैव विविधता की कमी के कारणवश कुपोषण और भुखमरी की समस्या गहरा गई है। अब यह स्पष्ट है कि अत्यधिक दोहन के परिणामस्वरूप प्रकृति द्वारा प्रदत्त यह विविधता लुप्त होने के गकार पर है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की पहल और राष्ट्रीय योजनाओं के समन्वय एवं सहयोग के कारण आज लगभग 7.4 मिलियन पौध जननद्रव्यों का संग्रह राष्ट्रीय और वैश्विक जीन बैंकों में संरक्षित किया जा सका है। भारत में स्थित विश्व के दूसरे सबसे बड़े जीनबैंक में 0.4 मिलियन एक्स सीटू 1800 पौधों की किस्मों व उनके वनस्पति संबंधितों के जननद्रव्यों को संरक्षित किया गया है। यह भी चिंता जाहिर की जा रही है कि वर्तमान में संसाधनों या उपयोगिता संबंधित सूचनाओं के अभाव में ज्यादातर उपलब्ध जैवविविधता का उपयोग अत्यंत कम हुआ है। इस कारणवश कृषि जैवविविधता अनुसंधान को मजबूत बनाने के लिए नीति निर्माताओं को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

कांग्रेस में जीन बैंकों के प्रभावी और कुशल, आनुवंशिक संसाधनों के क्षेत्रों में विज्ञान आधारित नवोन्मेष, आजीविका, फसल विविधता के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा, अल्प ज्ञात फसलों के प्रयोग और फसल सुधार में जंगली फसल संबंधितों की भूमिका को शामिल करना, संगरोध से संबंधित मुद्दें, जैव रक्षा व जैवसुरक्षा और ज्ञान संपदा अधिकारों तथा जननद्रव्य आदान-प्रदान करने के संदर्भ में पहुंच तथा लाभ साझा करने जैसे मुद्दों पर चर्चा और ज्ञान साझे किये जाएंगे। इस कांग्रेस के दौरान कृषि जैवविविधता के प्रभावी प्रबंधन एवं उपयोग में समस्त हितधारकों की भूमिका पर चर्चा हेतु जनमंच विकसित करने की भी योजना है।

भावी वैश्विक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तथा कृषि जैवविविधता का संरक्षण और विविध टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने में कृषि जैवविविधता का उपयोग एवं संरक्षण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

3. एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इंडेक्स पर होगी राज्यों की रैंकिंग

देश में कृषि क्षेत्र में व्यवसाय करना आसान बनाने के लिए सरकार ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इंडेक्स पेश किया है। अब राज्यों के बीच प्रत्येक वर्ष इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा होगी, जिससे देश में कृषि क्षेत्र में व्यवसाय के लिए माहौल बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

किसने तैयार किया है यह index

कृषि क्षेत्र में सुधारों पर इस तरह का पहला इंडेक्स नीति आयोग ने तैयार किया है।

Ranking

- इसमें महाराष्ट्र को किसानों के हितों के लिए सबसे अधिक कार्य करने वाला राज्य चुना गया है। इसके बाद गुजरात और राजस्थान हैं।
- इंडेक्स में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। इसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा और छत्तीसगढ़ हैं।

पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम, झारखंड, तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर सहित 29 राज्यों में से 20 का कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिहाज से प्रदर्शन खराब रहा।

Some other points about Index

- यह इंडेक्स राज्यों की ओर से कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए उठाए गए कदमों पर आधारित है।
- इंडेक्स का उद्देश्य राज्यों को कृषि क्षेत्र में समस्याओं की पहचान और उनका समाधान निकालने में मदद करना है। देश में इस क्षेत्र की वृद्धि दर कम है और किसानों को भी कम आमदनी की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
- इंडेक्स में मॉडल एपीएमसी एक्ट के सात प्रावधानों को लागू करने, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में शामिल होने की कोशिश (नाम-ई), मंडियों में टैक्स के लेवल को भी देखा जाएगा।

4. जैविक कृषि

जैविक कृषि एक समेकित कृषि है। इसके द्वारा जैव विविधता, जैविक चक्रण और मृदा जैविक कार्यकलाप संवर्धित होते हैं। जैविक कृषि के द्वारा सिंथेटिक उर्वरकों, विकासगत हार्मोनों, वृद्धिकारक एंटीबायोटिक पदार्थों, सिंथेटिक कीटनाशकों के इस्तेमाल के बिना फसलसंचालनों और पशुओं के लिए पर्यावरण अनुकूल वातावरण उत्पन्न होता है।

जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाएँ

जैविक कृषि की संभावना देखते हुए सरकार इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कृषि कार्यक्रम लागू कर रही है ताकि यहां के गांव के लोग खुशहाल हो सकें। ये योजनाएं हैं -

- मेरा गांव, मेरा गौरव
- राष्ट्रीय फसल बीमा योजना
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राष्ट्रीय बागवानी मिशन
- कृषि विज्ञान केन्द्रों का सुदृढीकरण और
- कृषि शिक्षा का विस्तार।

WHERE STATES STAND

States & Union Territories in terms of agriculture marketing & farm friendly reforms

TOP 5

Rank	States/UTs	Score
1	Maharashtra	81.7
2	Gujarat	71.5
3	Rajasthan	70.0
4	Madhya Pradesh	69.5
5	Haryana	63.3

BOTTOM 5

Rank	States/UTs	Score
30	Puducherry	4.8
29	Delhi	7.3
28	Jammu & Kashmir	7.4
27	Lakshwadeep	7.4
26	Meghalaya	14.3

Source: Agriculture Marketing & Farmer Friendly Reforms Index

5. वैश्विक राजस्थान कृषि तकनीक सम्मेलन)'Global Rajasthan agri tech. meet 'GRAM'):

Objectives

- कृषि से संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास का रास्ता प्रशस्त करना तथा किसान समुदाय के सामने विश्व में कृषि क्षेत्र से संबंधित सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को सामने लाना।
- किसानों समुदाय को विश्व भर में फैली निवेश प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना।

ग्लोबल एग्रीटेक सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बनाई गई योजनाओं का विवरण दिया जो निम्नांकित है-

1. प्रत्येक खेत को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए-**प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना**
2. जैविक खेती के तहत अधिक से अधिक क्षेत्र को खेती के तहत लाने के लिए **परंपरागत कृषि विकास योजना**

3. किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए **राष्ट्रीय कृषि बाजार, ईनाम-** की शुरूआत की गई है। ई नाम की शुरूआत-14 अप्रैल, 2016 से की गई है तथा 8 राज्यों के 21 मंडियों को इसमें कवर किया गया है। अभी तक 10 राज्यों में स्थित सभी 250 मंडियों को ई नाम से जोड़ दिया गया- है।

4. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की राजस्थान के सूरतगढ़ में शुरूआत की गई है। मार्च, 2017 तक 14 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लक्ष्य मुकाबले आज की तारीख तक 3.15 करोड़ कार्डों का वितरण कर दिया गया है। यह योजना किसानों के लिए उर्वरकों के उपयुक्त उपयोग से संबंधित सटीक निर्णय लेने के लिए सुगम है।

5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।

6. स्वदेशी गोजातीय प्रजातियों के विकास एवं संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरूआत की गई है जिससे कि वैज्ञानिक पद्धति के साथ स्वदेशी गोजातीय प्रजातियों के विकास एवं संरक्षण के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

7. सरकार ने मछली पालन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए नीली क्रांति की शुरूआत की है क्योंकि इसका मछुआरों, महिला मल्लाहों एवं जल जीव पालन से जुड़े लोगों की आजीविका को बेहतर बनाने में काफी योगदान है।

8. मेरा गांव मेरा गौरव के तहत ग्रामीण कृषि व्यवसाय को वैज्ञानिक खेती बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के कृषि विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा।

9. सरकार ने मौसम विज्ञान विभाग से संबंधित एक पूर्वानुमान प्रणाली की स्थापना करने, वैज्ञानिकों एवं किसानों का क्षमता निर्माण करने तथा किसानों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया है।

विशेष तथ्य:- नीति आयोग ने राजस्थान को वर्ष 2016 के लिए कृषि विपणन एवं किसान केंद्रित बेहतर सूचकांक से संबंधित श्रेणी में तीसरा स्थान प्रदान किया है। राज्य की कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन नीति 2015 कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन को प्रेरित करती है। यह कटाई उपरांत परिदृश्य में होने वाले नुकसानों में कमी लाती है तथा कृषि विपणन के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है।

6. अब सूखे से प्रभावित न होने वाली कृषि का समय आ गया है

सिंचाई पर केन्द्रण क्यों :

सिंचाई क्षेत्र में छह दशकों के निवेश के बावजूद सुनिश्चित सिंचाई के तहत 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि में से केवल 45 प्रतिशत ही कवर हो पाई है।

पिछले दो वर्षों में दस राज्यों में गंभीर सूखा पड़ा, जिससे कृषि क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा और वस्तुओं की कीमते बढ़ी हैं। वर्षा आधारित कृषि भूमि के अतिरिक्त छह लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के अंतर्गत लाने के लिए योजना के कार्यान्वयन के पहले एक वर्ष में पांच हजार तीन सौ करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है

योजना इस सन्दर्भ में

- हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) 'हर खेत को पानी' देने पर ध्यान केन्द्रित करने की दिशा में एक सही कदम है। इसके अंतर्गत मूल स्थान पर जल संरक्षण के जरिए किफायती लागत और बांध आधारित बड़ी परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा।
- भारत की अगले पांच वर्षों में सिंचाई योजनाओं पर 50 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इसलिए देश में सूखे के प्रभाव को कम करना कार्यान्वयन प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु बन गया है।
- वर्तमान में चल रही तीन योजनाओं- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम और खेत में जल प्रबंधन योजनाओं का विलय कर पीएमकेएसवाई बनाई गई है।
- PMKVY का उद्देश्य : इसका उद्देश्य न केवल सिंचाई कवरेज बढ़ाना, बल्कि खेती के स्तर पर जल के उपयोग की दक्षता बढ़ाना भी है। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि इस योजना से लगभग पांच लाख हेक्टेयर भूमि में ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा मिलेगा।
- अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मौजूदा जल निकायों और पारम्परिक जल स्रोतों की भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी। पानी की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए निजी एजेंसियों, भूजल और कमान क्षेत्र विकास के अतिरिक्त संसाधनों से पानी लेने का प्रयास भी किया गया। हालांकि यह सुनिश्चित करना गंभीर चुनौती है कि मौजूदा तीस मिलियन कुंओं और ट्यूबवेल से अतिरिक्त भूजल स्रोत का दोहन न हो। इस संदर्भ में देश के प्रत्येक खेत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल संरक्षण और जल की बर्बादी कम करना महत्वपूर्ण है। इससे स्थायी जल संरक्षण और जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की आदत बनेगी, जो नई सिंचाई सुविधाओं जितनी ही महत्वपूर्ण है। सिंचाई जल आपूर्ति के लिए कई विधियों से नगर निगम के गंदे पानी का शोधन कर उसे दोबारा उपयोगी बनाने की भी योजना है
- एक ऐसा देश जहां सूखा पड़ने का इतिहास रहा है, वहां केवल ऐसी पहलो से ही सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा। वर्ष 1801 से लेकर 2012 तक देश में 45 बार गंभीर सूखा पड़ा है। हाल के कमजोर मानसून का असर कृषि क्षेत्र पर पड़ा है और लगातार दूसरे वर्ष कृषि क्षेत्र का योगदान कम दर्ज किया गया। इसका बुरा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, जिसकी वजह से यह तर्क पुष्ट होता है कि सूखे के असर को कम करने से अर्थव्यवस्था पर कृषि का बुरा प्रभाव कम पड़ेगा।

Why to minimize use of water in agriculture

- आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 में कृषि में बदलाव की बात करते हुए संकर और उच्च उपज बीज, प्रौद्योगिकी और मशीनीकरण पर अनुसंधान में अधिक निवेश कर सूक्ष्म सिंचाई के जरिए जल का किफायती उपयोग करने का प्रस्ताव किया गया है।
- जलवायु परिवर्तन के खतरों को देखते हुए उत्पाकदता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जलवायु स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान पर निवेश की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया गया है।
- पानी की कमी बने रहने से भारतीय कृषि क्षेत्र में काफी समय से 'उच्च निवेश, उच्च जोखिम' की स्थिति है। कृषि क्षेत्र में अधिक पानी की खपत वाली फसलों के कारण जलवायु अनिवार्यता और बढ़ गई है।

- जब तक अनुकूल समर्थन मूल्य के साथ कम पानी की खपत वाली फसलों विशेष रूप से दलहनों और तिहलनों पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया जाता है, तब तक लगभग 98 मिलियन हेक्टेयर वर्षा आधारित खेत कृषि क्षेत्र में वृद्धि के लिए योगदान नहीं कर सकते।
- इसलिए पानी की दीर्घावधि आवश्यकता की पूर्ति के लिए समग्र विकास के परिप्रेक्ष्य में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 'विकेन्द्रिकृत राज्य स्तरीय नियोजन और कार्यान्वयन' को बढ़ाकर व्यापक जिला सिंचाई योजनाओं तक किया जाना चाहिए। यह कार्य केवल स्थानीय जल संसाधनों का संरक्षण और सुरक्षित करना ही नहीं है, बल्कि वितरण नेटवर्क को दक्ष बनाना है, ताकि कठिनाई के समय में भी खेतों में फसल की उत्पादकता को कायम रखा जा सके।

PMKVY and Carbon credit:

- 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद का 30 से 35 प्रतिशत तक कार्बन उत्सर्जन कम करने की प्रतिबद्धता के कारण भारत को पीएमकेएसवाई के अनुरूप विकेन्द्रिकृत जल प्रबंधन अपनाकर वृहद सिंचाई परियोजनाओं में कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा। हालांकि इन योजनाओं का अधिक लाभ तभी मिल पाएगा, जब यर्थावादी खेती के जरिए जैविक कार्बन मिट्टी को बढ़ाए, कार्बन स्टॉक मिट्टी की नमी बनाए रखे और जलवायु के प्रभाव से फसल की बर्बादी को कम किया जा सके।
- Decentralize irrigation इस संदर्भ में विकेन्द्रिकृत जलागम विकास के माध्यम से सामुदायिक पानी प्रबंधन, पारम्परिक टैंक प्रणाली और 'मिट्टी में नमी बढ़ाने' के लिए सुधार के जरिए 'पानी की उपलब्धता' कायम रखना महत्वपूर्ण है।
- यह प्रयास ग्रामीण इलाकों में सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भूजल भंडारण मूल स्थान पर मिट्टी को वास्तविक जलाशयों में परिवर्तित कर देता है, जो जलवायु के खतरों से असाधारण बचाव करता है।
- नीति आयोग के अंतर्गत अंतर मंत्रिमंडलीय राष्ट्रीय स्थायी समिति का गठन किया गया है, हालांकि यह देखना होगा कि राज्य स्तर के विभिन्न विभाग पीएमकेएसवाई के महत्वकांक्षी परिणाम हासिल करने में जमीनी स्तर पर कैसा सहयोग करते हैं।

Prelims/ Miscellaneous

GENERAL STUDIES HINDI

1. केरल को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया :

- स्वच्छ भारत अभियान) एसबीएम) (ग्रामीण (के अंतर्गत केरल को अब तक तीसरा और सबसे बड़ा खुले में शौच से मुक्त) ओडीएफ (राज्य घोषित किया गया है।
- सिक्किम) 6 लाख) और हिमाचल प्रदेश (70 लाख के बाद करीब (3.5 करोड़ की ग्रामीण आबादी के साथ खुले में शौच से मुक्ति का दर्जा प्राप्त करने वाला केरल सबसे बड़ा राज्य है।
- खुले में शौच से मुक्ति विशेष रूप से बच्चों में जल जनित बीमारियों से बचाव से जुड़े स्वास्थ्य लाभ और महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षा और सम्मान प्रदान करती है।

2. 'फिल्म प्रोत्साहन कोष' : अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए

सरकार ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए एक 'फिल्म प्रोत्साहन कोष' बनाने की दिशा में एक नई पहल की है। इस पहल से स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को विश्व भर में अपनी रचना का प्रचार करने में मदद मिलेगी।

How will it be used

फिल्म प्रोत्साहन कोष से उन फिल्मों के प्रचार संबंधी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनका चयन किसी जानेमाने अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के किसी भी प्रतिस्पर्धा खंड के लिए किया जाएगा अथवा जो विदेशी फिल्म श्रेणी के तहत एकेडमी अवार्ड्स के लिए भारत की आधिकारिक मनोनीत फिल्म होगी। सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों के एक पैनल की सिफारिशों पर आधारित इस पहल पर अमल के लिए फिल्म समारोह निदेशालय को प्रमुख एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

3. प्रोग्रेस पंचायत

- 9 सितंबर 2016 को हरियाणा के मेवात जिले से शुरू की गई
- इसका मकसद आम लोगों को अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी देना और विकास के लिए धन के इस्तेमाल के बारे में उनकी राय लेना है लोगों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में विकास योजनाओं एवं रोजगार के बारे में जानकारी देना है।
- साथ ही समुदाय के बीच गलत धारणा को दूर करना है।

4. हर्बल दवाओं के लिए 9वें अंतरराष्ट्रीय नियामक सहयोग बैठक

- आयुष मंत्रालय हर्बल दवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय नियामक सहयोग की (आईआरसीएच) 9 वीं वार्षिक बैठक का 8 से 10 नवंबर, 2016 तक नई दिल्ली के अशोका होटल में आयोजन कर रहा है।
- **स्थापना** : हर्बल दवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय नियामक सहयोग की स्थापना (आईआरसीएच) 2006 में हुई थी जो हर्बल दवाओं के नियमन के लिए जिम्मेदार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सृजित नियामक प्राधिकारियों का एक वैश्विक नेटवर्क है। (डब्ल्यूएचओ)
- **उद्देश्य** : इसका उद्देश्य हर्बल दवाइयों के उन्नत विनियम द्वारा जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना है।

5. स्वच्छ भारत महिला सम्मेलन ने स्वच्छता महिला चैंपियनों को सम्मानित

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने आज स्वच्छ भारत मिशन की महिला चैंपियनों का सम्मेलन आयोजित किया। (ग्रामीण) यह आयोजन ग्रामीण स्वच्छता में महिलाओं के योगदान को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए किया गया था। के सहयोग से आ(यूनीसेफ) सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र बाल कोषयोजित किया गया और इसका उद्देश्य श्रेष्ठ व्यवहारों को साझा करना , स्वच्छ भारत मिशन में नेतृत्व की भूमिका निभा रही महिलाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना (ग्रामीण) और सम्मानित करना है।

6. पांच राज्यों के आठ शहरों और चंडीगढ़ को जन परिवहन को प्रोत्साहन के सम्बंध में बेहतरीन शहर करार दिया

- पांच राज्यों के आठ शहरों और केंद्र शासित चंडीगढ़ को जन परिवहन, नॉन मोटराइज्ड-शहरों के रूप में चिन्हित 'प्रशंसनीय' और 'उत्कृष्ट' यातायात तथा सड़क सुरक्षा के सम्बंध में किया है।

- इनमें गुजरात के सूरत, गांधीनगर और राजकोट, मध्यप्रदेश के इंदौर और जबलपुर, कर्नाटक का धारवाड़, हरियाणा का करनाल तथा सिक्किम की राजधानी गंगटोक शामिल हैं।
- बेहतरीन जन शहरी यातायात 'उत्कृष्ट' वर्ग में सूरत के एकीकृत जन यातायात प्रणाली को '
- अल्पकालिक जन यातायात के लिये सिंहस्थ को चुना गया है।
- इंदौर को 2016 के लिये करने के लिये चुना गया है। 'प्रशंसनीय पहल'
- गांधीनगर के जी वर्ग के लिये चुना गया 'प्रशंसनीय पहल' बाइक और करनाल के सांझी साइकिल पहलों को- है।
- इसी तरह कर्नाटक की धारवाड़ के लिये बेहतरीन और गुजरात के 'सिटी बस सेवा' हुबली सेवा सम्बंधी- राजकोट को प्रशंसनीय पहल के लिये चुना गया है।
- गंगटोक की एकीकृत डिपो प्रबंधन प्रणाली और जबलपुर के को प्रशंसनीय पहल वर्ग के लिये चुना 'कार्ड-जे' गया है।



GENERAL STUDIES HINDI